न्यायामूर्ति एन. के. सोधी और एन. के. सूद के समक्ष

सुरिंदर कुमार,-याचिकाकर्ता।
बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र,-प्रतिवादी।
1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16759
26 अक्टूबर, 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—योग्यता—नियुक्ति—नियुक्ति के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत—क्या उम्मीदवार को पात्र बनाने के लिए पूर्णांकन किया जा सकता है—उम्मीदवार के पास आवश्यक प्रतिशत से कम था—सेवाएं समाप्त—उसे चुनौती—माना गया कि अंकों के प्रतिशत को पूर्णांकित करने को ध्यान में रखा जाए पूर्ण पीठ का निर्णय स्वीकार्य नहीं - सेवा समाप्ति में विश्वविद्यालय की कार्रवाई बरकरार।

यह प्रश्न कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को 'राउंड ऑफ' करने का लाभ दिया जा सकता है ताकि उसे किसी पद पर चयन के लिए पात्रता क्षेत्र के भीतर लाया जा सके, कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था और इसका उत्तर नकारात्मक में दिया गया था। श्री के.धरन, मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) बेंच के लिए बोलते हुए फैसले के पैरा 19 में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहा: -

“किसी पद पर चयन के लिए किसी उम्मीदवार को पसंद के क्षेत्र में लाने के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को पूरा करने की विधि कानून द्वारा आवश्यक नहीं है।हमारा यह भी विचार है कि परीक्षा/परीक्षा में प्राप्त प्रतियोगिता के अंकों पर किसी भी पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अब अगली पूरी संख्या को पूरा किया जाना है, जब तक कि चयन को नियंत्रित करने वाले नियम में विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो।”

पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित आदेश के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता कानून में व्याख्याता के पद के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसके पास न्यूनतम प्रतिशत अंक नहीं थे।

(पैरा 5 और 6)

याचिकाकर्ता की ओर से बलराम के. गुप्ता, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता वी. एस. राणा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एस. सी. सिब्बल।

निर्णय

माननीय एन. के. सोधी,

(1) कानून का सामान्य प्रश्न जो चार रिट याचिकाओं के इस समूह में उठता है, जिन्हें एक साथ सुनने का आदेश दिया गया था, वह यह है कि क्या किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अंकों के प्रतिशत को पूर्णांकित किया जा सकता है ताकि उम्मीदवार को भी पात्र बनाया जा सके। हालाँकि उसके अंकों का वास्तविक प्रतिशत आवश्यकता से कम है। इन याचिकाओं को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-
सी. डब्ल्यू. पी. 1997 का 16759 और 16882

(2) पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि इन याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के प्रश्न समान हैं और " सी. डब्ल्यू. पी" 16759 में निर्णय अन्य रिट याचिका को भी नियंत्रित करेगा। तर्कों को 1997 के सीडब्ल्यूपी 16759 में संबोधित किया गया था और इसलिए, इस मामले से तथ्य लिए जा रहे हैं।

(3) याचिकाकर्ता को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संक्षेप में विश्वविद्यालय) में कानून में अंशकालिक व्याख्याता नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति को इसकी कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। अंशकालिक व्याख्याता के रूप में काम करते हुए याचिकाकर्ता ने उसी विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी की। विधि विभाग में व्याख्याताओं के कुछ पद खाली हो गए और चयन समिति की सिफारिश पर उन पदों के खिलाफ छह अन्य के साथ याचिकाकर्ता का चयन किया गया। याचिकाकर्ता को 7 सितंबर, 1994 को 2200-4000 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय के नियमों के तहत वेतनमान में स्वीकार्य सामान्य भत्ते भी हैं। भले ही उनकी नियुक्ति अस्थायी थी लेकिन यदि उनका कार्य और आचरण असंतोषजनक नहीं पाया गया तो इसके जारी रहने की संभावना थी। दोनों ओर से एक महीने के नोटिस पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति पत्र में यह भी निर्धारित किया गया था कि "यदि पद पर आसीन व्यक्ति पहले कार्यभार ग्रहण करता है तो नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है"। हालाँकि, कार्यकारी परिषद ने 4 नवंबर, 1997 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए। संचार के साथ एक महीने की अग्रिम सूचना अवधि के वेतन का चेक भी भेजा गया था। कार्यकारी परिषद के इस फैसले के खिलाफ ही याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई मनमानी है।

(4) विश्वविद्यालय की ओर से दायर जवाब में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कानून में व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने का योग्य नहीं था क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों का न्यूनतम प्रतिशत नहीं था ।
(यूजीसी)। यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के बाद विश्वविद्यालय ने न्यूनतम अंकों के प्रतिशत के संबंध में शर्त में ढील देने के लिए उसका मामला यूजीसी को भेज दिया था, लेकिन यूजीसी इसमें ढील देने के लिए सहमत नहीं था। चूंकि ढील नहीं दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाओं को उसके रोजगार की शर्तों के अनुसार समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

(5) विश्वविद्यालय और यू. जी. सी. द्वारा व्याख्याता के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता "कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर समकक्ष ग्रेड या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होना " आम बात है। यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से 950 में से 522 अंक प्राप्त करके अपनी एल. एल. एम. परीक्षा उत्तीर्ण की। इससे मास्टर डिग्री स्तर पर उनके अंकों का प्रतिशत 54.95 (सटीक रूप से 54.947) से कम हो जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि 54.94% अंकों को 55 प्रतिशत तक पूरा किया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि 54.94% अंकों को 55% तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो याचिकाकर्ता के पास मास्टर डिग्री स्तर पर अंकों का अपेक्षित प्रतिशत था और इस प्रकार, वह नियुक्ति के लिए पात्र था। याचिकाकर्ता के वकील डॉ. बलराम गुप्ता ने अपनी याचिका के समर्थन में **राकेश कुमार बनाम गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और अन्य** [1] में इस न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का उल्लेख किया। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम पहले सिद्धांतों पर इस मुद्दे की जांच करें कि क्या अंकों के प्रतिशत को पूरा किया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ता को पात्र बनाया जा सके क्योंकि मामला रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती द्वारा समाप्त होता है। यह प्रश्न कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को राउंड ऑफ करने का लाभ दिया जा सकता है ताकि उसे किसी पद पर चयन के लिए पात्रता क्षेत्र के भीतर लाया जा सके, **कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** [2]में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था और इसका उत्तर नकारात्मक में दिया गया था। श्री के.धरन, मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) बेंच के लिए बोलते हुए निम्नानुसार कहा गया:

“नियम 7 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। 33% चट्टान के नीचे के निशान उसमें तय किए गए हैं। इसी तरह वाइवा-वॉयस टेस्ट के लिए बुलाए जाने के लिए सभी पेपरों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। हमारे अनुसार, नियम में ऐसे उम्मीदवार को योग्य बनाने की संभावना की परिकल्पना नहीं की गई है, जिसने प्रत्येक पेपर में 33 प्रतिशत और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए हैं, जिसे वाइवा-

1 1989(2) RSJ 570
2 1997 (5)SLR 133

वॉयस टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। 33% या 50 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, नहीं है

अंकों के प्रतिशत को पूरा करने के आधार पर मूल्यांकन किया जाना।

यदि अंकों को पूरा किया जाता है और प्रतिशत को नहीं, तो प्रीमियम इस चौंकाने वाली सीमा तक नहीं जाएगा, एक व्यक्ति जिसने एक पेपर में 65.5 अंक प्राप्त किए हैं, वह इसे अगले पूर्ण अंक में पूरा करने का लाभ ले सकता है। इस तरह की प्रक्रिया का परिणाम अंकों के प्रतिशत को पूरा करने जितना चौंकाने वाला नहीं हो सकता है। यदि केवल वास्तविक अंकों को पूरा करने का सहारा लिया जाता है, तो एक व्यक्ति जिसने 449.5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वह अकेले 450 अंक प्राप्त करने वाला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त विस्तृत स्थिति में एक उम्मीदवार को मिलने वाले कुल लाभ एक या अधिकतम दो अंकों के होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसा लाभ नहीं दिया जाना चाहिए जब शैक्षणिक रूप से योग्य व्यक्ति प्रतिस्पर्धी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। उच्च प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में 0.1 प्रतिशत अंक भी बहुत मायने रखते हैं।"

पुनः निर्णय के पैरा 19 में विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

"किसी पद पर चयन के लिए किसी उम्मीदवार को पसंद के क्षेत्र में लाने के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को पूरा करने की विधि कानून द्वारा आवश्यक नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि परीक्षा/परीक्षा में प्राप्त प्रतियोगिता के अंकों पर किसी भी पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अब अगली पूरी संख्या को पूरा किया जाना है, जब तक कि चयन को नियंत्रित करने वाले नियम में विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो।"

(6) पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता कानून में व्याख्याता के पद के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसके पास स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम प्रतिशत अंक नहीं थे।

(7) राकेश कुमार के मामले (ऊपर) में, याचिकाकर्ता को एक निजी कॉलेज में अंग्रेजी में व्याख्याता नियुक्त किया गया था, जिसकी नियुक्ति के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने की आवश्यकता थी। उनकी नियुक्ति के समय पात्रता एम.ए. परीक्षा में 50% अंक थी। जबकि अनुमोदन का मामला लंबित था, विश्वविद्यालय ने अपने पहले के निर्णय में संशोधन किया और न्यूनतम अंक बढ़ाकर 55% कर दिया और संशोधित निर्णय के आधार पर अनुमोदन देने से इनकार कर दिया। डिविजन बेंच ने रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को रद्द कर दिया और उसे मंजूरी देने का निर्देश दिया क्योंकि नियुक्ति की तारीख के अनुसार पात्रता के आधार पर मंजूरी दी जानी थी।
यह भी पाया गया कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई न्यथा उचित नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने एमए में 54.6% अंक प्राप्त किए थे, जिसे 55% करने के लिए पूर्णांकित किया जाना था। डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

" हम मौजूदा मामले में प्रतिशत के बारे में इतना सख्त होने के विश्वविद्यालय के रुख की सराहना नहीं करते हैं क्योंकि राउंडिंग ऑफ एक सिद्धांत है जिसे लगभग हर जगह मान्यता प्राप्त है और विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को भी पात्र बनाने की सलाह दी गई होगी।

ये टिप्पणियाँ याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करती हैं, लेकिन चूंकि वे कुलदीप सिंह के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ के फैसले के विपरीत हैं, इसलिए इन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए, भले ही पूर्ण पीठ ने इस मामले पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। कुलदीप सिंह के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, हमें याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(8) तब यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने से पहले कार्यकारी परिषद ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया था और न ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया था और इसलिए, आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। विद्वान वकील ने इस तर्क के

समर्थन में **बासुदेव तिवारी बनाम सिडो कान्हू विश्वविद्यालय और अन्य** [3]मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया।हम इस विवाद में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं।याचिकाकर्ता एक अस्थायी कर्मचारी था और उसकी सेवाओं को नियुक्ति पत्र में निहित शर्तों अनुसार समाप्त किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी।इसके अलावा, हमारे सामने उस मामले में कोई विवाद नहीं है जिसका निपटारा किया जाना था, जिसके लिए नोटिस जारी करना आवश्यक था।बसुदेव तिवारी के मामले (ऊपर) में उनके प्रभुता का निर्णय अलग-अलग तथ्यों पर है और याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

(9) याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में एलएलएम परीक्षा में प्राप्त अंकों को पूर्णांकित कर दिया था और कहा था कि उसके खाते में 55% अंक हैं जबकि ऐसा नहीं था। जब विश्वविद्यालय को पता चला कि उसे केवल 54.947% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसने छूट देने के लिए उसके मामले को यूजीसी के पास भेज दिया। बेशक, छूट नहीं दी गई और इसलिए, विश्वविद्यालय के पास नियुक्ति पत्र के अनुसार उनकी सेवाएं समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस कारण भी विश्वविद्यालय की आक्षेपित कार्यवाही में कोई दोष नहीं पाया जा सकता

(3) जेटी1998 (6) एससी 464

1997 का सी. डब्ल्यू. पी. 17094 और 1998 का 42

(10) इन रिट याचिकाओं में चुनौती रामेश्वर दास मेहला प्रतिवादी 3 की नियुक्ति के लिए है जिन्हें विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया है।

(11) 1997 के एक विज्ञापन संख्या 2 द्वारा विश्वविद्यालय ने सभी योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक लाइब्रेरियन के पद का विज्ञापन किया।आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त, 1997 थी।इस पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ, अन्य के अलावा, पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/डी. डीक्यूमेंटेशन में मास्टर डिग्री कम से कम पचास प्रतिशत (55 प्रतिशत) अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड और लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए। लगातार अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के मानदंड को पूरा करने के लिए एक उम्मीदवार को मास्टर डिग्री से पहले दो निचली परीक्षाओं में से प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक या दो निचली परीक्षाओं में से औसतन 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी 3 ने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस परीक्षा में 800 में से 439 अंक प्राप्त किए जो 55% से कम हैं, सटीक प्रतिशत 54.8 आता है। उनके मामले में विश्वविद्यालय ने अंकों को 55% तक पूर्णांकित कर दिया और उन्हें पात्र माना और उन्हें पद के लिए उपयुक्त पाया और उन्हें 4 नवंबर, 1997 के नियुक्ति पत्र के अनुसार इस पद पर नियुक्त किया गया। 19981998 के सीडब्ल्यूपी 42 में याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसके बी.ए. में 49.7% अंक थे। और यदि इन्हें 50% तक पूर्णांकित कर दिया जाता तो वह अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड की कसौटी पर खरे उतरते और पद के लिए पात्र हो जाते, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनके मामले में अंकों को पूर्णांकित नहीं किया और उन्हें अयोग्य माना। 1997 के सीडब्ल्यूपी 17094 में याचिकाकर्ता को भी इस पद के लिए अयोग्य पाया गया क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में डिप्टी लाइब्रेरियन के रूप में 10 साल का अनुभव या कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में 15 साल का अनुभव नहीं था, जो पद पर नियुक्ति के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी। दोनों ही मामलों में याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी अयोग्य होने के कारण खारिज कर दी गई।

(12) अब प्रतिवादी 3 की नियुक्ति पर आते हैं। हमारा मानना है कि इसे कायम नहीं रखा जा सकता। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वे 55% से कम थे। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वे 54.8% थे। विश्वविद्यालय द्वारा उसे पात्र बनाने के लिए इन अंकों को 55% तक पूर्णांकित करना उचित नहीं था। यह कुलदीप सिंह के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित आदेश के विपरीत है। प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील ने लाइब्रेरियन के रूप में प्रतिवादी 3 की नियुक्ति को उचित ठहराने की कोशिश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उपायों के संबंध में यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को जारी 24 दिसंबर, 1998 की अधिसूचना पर भरोसा करने की मांग की। मानकों के रखरखाव के लिए जिसके अनुसार मौजूदा पदधारियों के लिए लाइब्रेरियन सहित कुछ पदों के लिए 55% अंकों की न्यूनतम आवश्यकता पर जोर नहीं

3 JT 1998 (6)SC 464

दिया जाना चाहिए जो पहले से ही विश्वविद्यालय प्रणाली में हैं।

यह यह अधिसूचना, जो बहस के दौरान पेश की गई थी, हमारी राय में, प्रतिवादी 3 की नियुक्ति को नियंत्रित नहीं करेगी, जो उस वर्ष जारी विज्ञापन के जवाब में नवंबर, 1997 में की गई थी। जिस यूजीसी की अधिसूचना पर भरोसा किया गया वह दिसंबर, 1998 में जारी की गई थी। वर्ष 1998 में जारी की गई यह अधिसूचना वर्ष 1997 में की गई नियुक्ति को मान्य नहीं कर सकती है जो तब अमान्य थी। यह सच है कि इन दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता पद के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन यह विश्वविद्यालय को प्रतिवादी 3 का चयन करने के लिए उचित नहीं ठहराता है जो अयोग्य था।

(13). यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 1997 के सीडब्ल्यूपी 16759 और 16882 में याचिकाकर्ताओं के मामले में विश्वविद्यालय ने उनके अंकों के प्रतिशत को पूर्णांकित करने से इनकार करके और सीडब्ल्यूपी में याचिकाकर्ता के मामले में भी उन्हें कानून में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 1998 के 42 जबकि इसने 1997 के सीडब्ल्यूपी 17904 और 1998 के 42 में प्रतिवादी 3 के मामले में एक अलग मानदंड अपनाने का फैसला किया और उसे पात्र बनाने के लिए उसके अंकों को पूर्णांकित किया। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

(14). परिणाम में, 1997 के सीडब्ल्यूपी और 16759 और 16882 बिना किसी योग्यता के हैं और इसे खारिज कर दिया गया है, जबकि 1997 के सीडब्ल्यूपी 17094 और 1998 के 42 को अनुमति दी गई है और विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के रूप में रामेश्वर दास मेहला की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करे।
जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरूग्राम, हरियाणा